



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान अविचल चतुर्वेदी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

‘अगले माह सवा लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित की जायेगी’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग के काम की समीक्षा की

जयपुर, 25 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के साथ ही, खाली पदों पर भर्ती तथा स्कूलों में कक्षा-कक्षा का निर्माण कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि हम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को माॅडल स्टेट बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सर्वे करा कर विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति करें तथा राज्य के सरकारी व निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एक रूपता लाई जाये।

कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चले, इस हेतु सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को लगभग साढ़े 3 करोड़ पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया है तथा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों एवं 9 से 12 तक की बालिकाओं को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि आगामी माह में 1 लाख 25 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु सरकार खाली पदों पर भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अब तक लगभग साढ़े 20 हजार पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और लगभग 18 हजार पदों पर पदोन्नति की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का सर्वे करवाकर, विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एक रूपता लाई जाए।

मुख्यमंत्री ने स्कूलों में कक्षा कक्षाओं तथा बालिका विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति का भीतिक सत्यापन कर

आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मत और नव निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भीतिक सत्यापन के कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में शासन सचिव स्कूल शिक्षा, कृष्ण कुणाल ने मुख्यमंत्री को स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के 1.34 करोड़ विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस अवसर पर, स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, अविचल चतुर्वेदी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी सहित स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

‘आरोप अडानी पर है, और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों, जिनमें अन्य राज्यों से आये लोग भी शामिल थे, ने भाग लिया। ये लोग अडानी के खिलाफ नारे लिखी हुई तख्तियों हाथों में उठाये हुये थे। अमेरिकन प्रॉसिक्यूटर्स ने सागर अडानी पर आरोप लगाते हुये कहा कि उन्होंने कथत रूप से करोड़ों डॉलर की रिशत भारतीय अधिकारियों को दी। इन नोटों को प्रॉसिक्यूटर्स ने “रिशत के नोट” बताया है। इस कथित रिशत-कांड पर अमेरिकन अधिकारियों का ध्यान उस समय गया, जब अडानी की कम्पनी 2021 में शुरू हुये इस लेन-देन से सम्बन्धित पैसों की उगाही अमेरिकन निवेशकों से कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि रिशत के इस अभियोग की शाखें पूरी दुनिया में फैल गई हैं। ऐसी खबरें हैं कि कुछ बैंकर इस गुप को नया उधार देना फिलहाल रोक देने पर विचार कर रहे हैं।

खुली जेल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) वाले कैदियों का भी पुनर्वास करना होगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा कि खुली जेल को आवंटित की गई जमीन को कम नहीं किया जा रहा है। खुली जेल का कुल क्षेत्रफल 61,160 वर्ग मीटर है। इसमें से 17,800 वर्ग मीटर जमीन पर निर्माण है। वहीं, खुली जेल के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से 14,940 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करना प्रस्तावित है, जबकि 22,000 वर्ग मीटर जमीन पर ही सेटिलाइट हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। वहीं, हॉस्पिटल निर्माण के दौरान कैदियों का पुनर्वास किया जाएगा। मौजूदा समय में खुली जेल में 410 कैदी रह रहे हैं।

दरअसल अवमानना याचिका में कहा था कि खंडपीठ ने 17 मई 2024 को आदेश जारी कर, राज्य सरकार को खुली जेल की जमीन को कम नहीं करने और छह दशक से खुली जेल के लिए काम आने वाली इस जमीन को संरक्षित करने के लिए कहा था, लेकिन जेडीए ने 30 जुलाई 2024 को इस जमीन पर सेटिलाइट हॉस्पिटल का आवंटन मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार व जेडीए का ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।

15 साल राज किया, पर 15 सीटों पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लें या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें, जो स्वतंत्र एवं सक्षम हो। मल्लिकार्जुन खड्गे निश्चित रूप से इस पद को सँभाल नहीं सके हैं, और उनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होगा, तो यह स्पष्ट है कि बैंक सीट ड्राइविंग आगे न तो काम कर सकती है और न करेगी। 2019 से लेकर अब तक, कांग्रेस ने बहुत सारे चुनाव हारे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक करने की दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई तथा न ऐसी नई प्रतिमाओं को आगे लाया गया, जो पार्टी

को ताकतवर बना सकें। पिछले पाँच साल का रिपोर्ट कार्ड इस प्रकार है- 2019 - लोक सभा हारे, 2019 - आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश तथा हरियाणा हारे 2020 - दिल्ली और बिहार हारे 2021 - असम, केरल तथा पश्चिम बंगाल हारे 2022 - गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा तथा मणिपुर हारे

2023 - राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ हारे 2024 - लोकसभा चुनाव, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तथा महाराष्ट्र हारे इन हारों के लिये क्या कोई जिम्मेदार उठराया गया? अब तक इन पराजयों की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, कोई आत्म-निरीक्षण नहीं किया गया, कोई विश्लेषण नहीं किया गया। एक हार के बाद, पार्टी दूसरी हार की ओर बढ़ जाती है।

संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्षता” शब्द शामिल किए जाने के खिलाफ याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने वर्षों बाद इस प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का क्रियान्वयन सरकार पर निर्भर है।
- ज्ञातव्य है कि आपातकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में “समाजवाद” व “धर्मनिरपेक्षता” शब्द जुड़ावा थे।
- भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय ने पृथक-पृथक याचिकाएं दायर कर इन शब्दों को हटाने की मांग की थी और कहा था कि आपातकाल में संसद द्वारा पारित संशोधन अमान्य हैं, पर कोर्ट ने उनके तर्क को ठुकरा दिया।

इतने वर्षों के बाद प्रक्रिया को इस तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि समाजवाद और

धर्मनिरपेक्षता क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है, यह सरकार की नीति पर निर्भर करेगा।

इस्तीफा प्रकरण : धारीवाल, महेश जोशी सहित 6 को हाईकोर्ट का नोटिस

भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका में 6 नेताओं से 4 सप्ताह में जवाब मांगा

जयपुर, 25 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के तत्कालीन 81 विधायकों द्वारा इस्तीफा देने से जुड़े मामले में, अपने और 75 विधायकों के इस्तीफे की कॉपी स्वीकर को सौंपने वाले तत्कालीन छह विधायकों, शांति धारीवाल, महेश जोशी, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी, रामलाल जाट व संयम लोढ़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने इन तत्कालीन विधायकों से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। चीफ जस्टिस, एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए

25 दिसम्बर 2022 को 81 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपे। अध्यक्ष ने लम्बे समय तक इस पर निर्णय नहीं लिया। पिछली सुनवाई पर स्वीकर की ओर से जवाब आया कि इस्तीफे स्वीच्छक नहीं थे, इसलिए अस्वीकार कर दिये। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि किसके दबाव में इस्तीफे दिये गये।

दिए। याचिकाकर्ता ने गत सुनवाई को इन तत्कालीन 6 विधायकों को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। याचिका में कहा गया कि 81 विधायकों ने 25 सितंबर, 2022 को विधानसभा स्वीकर को अपने इस्तीफे दिए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कई बार स्वीकर को प्रतिवेदन देकर इस्तीफों

पर निर्णय करने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को कहा गया कि इस्तीफा देने के बाद इन 81 विधायकों ने वेतन भत्तों के तौर पर करीब 18 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। ऐसे में इस बिन्दु पर उचित आदेश दिए जाएं। इसके अलावा स्वीकर के समक्ष लंबित इस्तीफों के संबंध में निर्णय करने की

अधिकतम समय सीमा तय की जाए। अधिवक्ता हेमन्त नाहटा ने बताया कि इन छह तत्कालीन विधायकों को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र इसलिए दायर किया था, ताकि पता चल सके कि कांग्रेस के 81 विधायकों ने किसके दबाव में विधानसभा स्वीकर को इस्तीफे सौंपे थे। दरअसल इस मामले में पिछली सुनवाई पर मौजूदा स्वीकर का जवाब आया था, जिसमें कहा गया था कि इस्तीफा देने के बाद इन 81 विधायकों ने वेतन भत्तों के तौर पर करीब 18 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। ऐसे में इस बिन्दु पर उचित आदेश दिए जाएं। इसके अलावा स्वीकर के समक्ष लंबित इस्तीफों के संबंध में निर्णय करने की

झारखंड की नई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है। इन 71 करोड़पतियों में से 28 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा, (जे.एम.एम.), 20 भाजपा, 14 कांग्रेस, 4 आर.जे.डी., 2 सी.पी.आई. एम.एल. लिबरेशन और एक-एक एल. जे.पी. (राम विलास), जय (यू.) तथा ए.जे.एस.यू. के हैं। हाल में संपन्न हुए चुनावों में जे.एम.एम. को 34 सीटों पर विजय हासिल हुई, जबकि कांग्रेस ने 16 सीटें जीतीं। वहीं, आर.जे.डी. ने चार और सी.पी.आई.एम.एल. लिबरेशन ने दो सीटें जीतीं हैं। दूसरी तरफ भाजपा को 21 विधानसभा सीटों पर तथा उसकी पार्टनर एल.जे.पी. (पासवान), जय (यू.) और ए.जे.एस.यू. पार्टी को एक-एक सीट पर जीत मिली। झारखंड विधानसभा 2024 में प्रति विजेता प्रत्याशी औसत संपत्ति 6.90 करोड़ है। सन् 2019 के चुनावों में यही औसत 3.82 करोड़ था।

अडानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) को “आधारहीन” बताया है। अडानी मुद्दे को लेकर ओ रहे हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई।

संभल : सपा सांसद और विधायक पुत्र के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज

संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक, सभी स्कूल बंद किये

संभल, 25 नवंबर। जिले में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल के दौरान हुई पथरावजी की घटना और पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में चार लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इलाके में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और पुलिस ने पूरे मामले को लेकर संभल कोतवाली में एफ.आई.आर. दर्ज की है। एफ.आई.आर. में सपा सांसद जिया उर रहमान और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। रविवार को जिले में दंगे के बाद के बाद संभल कोतवाली में हुए को लेकर दर्ज की गई एफ.आई.आर. में सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काने और भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के हाथ दंगा भड़काने वाले कुछ वीडियो पोस्ट भी लगे

सपा सांसद जिया उर रहमान तथा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल के खिलाफ साजिश करने, दंगा भड़काने व भीड़ इकट्ठी करने के आरोप हैं।

शिकायत दर्ज कराई है। जिया उर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने भीड़ को उकसाया था। उन्होंने बताया कि बर्क को पहले भी नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद उन्होंने लोगों को भड़काया, जिस वजह से लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बर्क को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संभल में बवाल के बाद कई तरह की पार्वदियां लगा दी गई हैं। इस के तहत एक दिवस तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक जिले में बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक है। प्रशासन ने अतिसंवेदनशील स्थिति को देखते हुए एच.कैम्प उठाया है। जानकारी के मुताबिक हिंसा और पथराव के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार बरामद हुए हैं।

दो से ज्यादा संतान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सुनवाई करते हुए दिए। प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि कार्मिक विभाग ने 16 मार्च, 2023 को अधिसूचना जारी कर दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को संबंधित सालों से पदोन्नत करने का प्रावधान किया था। इसके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने गत अगस्त माह में अंतरिम आदेश जारी कर पदोन्नतियों पर रोक लगा दी थी, जबकि अंतरिम आदेश के जरिए पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को पूर्व में दी गई पदोन्नति इस अधिसूचना से प्रभावित नहीं हो रही है। इसलिए पूर्व में दिए आदेश को वापस लिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पूर्व में दिए आदेश को संशोधित करते हुए तथा पदोन्नतियों पर लगी रोक को हटाने पर उसे याचिका के निर्णयाधीन रखा है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक जून 2002 या इसके बाद दो से ज्यादा संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को तीन व पांच अवसरों तक पदोन्नति से वंचित रख रखा था। वहीं, कार्मिक विभाग ने 16 मार्च 2023 को एक अधिसूचना निकाल कर कहा कि किसी भी कर्मचारी को केवल ज्यादा संतान होने के चलते पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिन कर्मचारियों को

पदोन्नति से वंचित किया है, उन्हें उनके पदोन्नति वर्ष से ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पिछली तारीखों से किसी भी कर्मचारी की योग्यता के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। वहीं, इस अधिसूचना के जरिए वो कर्मचारी पदोन्नत होंगे, जिन्हें पहले अयोग्य माना जा चुका है। इस कारण याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति पर प्रभावित होगी और वे वरिष्ठता में उनसे नीचे चले जाएंगे। इसलिए 16 मार्च 2023 की अधिसूचना के आधार पर दो से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जाए।

तेलंगाना ने अडानी का 100 करोड़ का दान लौटाया है। हैदराबाद, 25 नवंबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए.रेवंत रेड्डी ने सोमवार को देश के प्रमुख उद्योगपति गोतम अडानी से जुड़े विवाद पर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट की। रेड्डी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि तेलंगाना सरकार का कथित मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तथा अडानी, अडानी और टाटा जैसे उद्योगपति राज्य में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते, वे कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी द्वारा घोषित 100 करोड़ रुपये के दान को अस्वीकार करने का निर्णय लिया है।

केजरीवाल दिल्ली में 80 हजार नये बुजुर्गों को पेंशन देंगे। नई दिल्ली, 25 नवंबर। दिल्ली में अब से कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेलते हुए दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में 80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन की सीमागत मिलेगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में अब सब रूके हुए काम फिर से शुरू करारेंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुजुर्गों के लिए यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुजुर्गों के लिए यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, सरकार को

नीट यूजी : स्ट्रे वेकैन्सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सहित अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 11 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में बायोलाॅजी विषय का उल्लेख नहीं होने पर स्ट्रे वेकैन्सी राउंड में सीट आवंटन नहीं करने पर एकलपीठ में याचिका पेश हुई थी। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत दिनों अपीलार्थियों के सीट आवंटन को निरस्त कर दिया था, जबकि एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं को अगस्त माह में ही इसकी जानकारी थी कि काउंसिलिंग में वह प्रमाण पत्र पेश करना है, जिसमें कक्षा 11 वीं में

बायोलाॅजी विषय होने की जानकारी हो। वहीं, 9 व प्रक्रिया पूरी होने के बाद एकलपीठ में याचिका दायर की गई, जबकि स्ट्रे वेकैन्सी राउंड में अपीलार्थी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने 11 वीं कक्षा में बायोलाॅजी विषय होने के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया था और याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था। इसलिए उन्हें सीट आवंटित नहीं की गई। ऐसे में अपीलार्थियों का सीट आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। याचिका को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सीट आवंटन निरस्त करने पर रोक लगा दी है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की घोषणा को चतुर राजनीतिक कदम माना जा रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जब वे जेल में गये तब बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गयी थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से पेंशन शुरू करवायी है।